## दिनांक 13.05.2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि रोड मैप के परफॉरमेंस इंडिकेटर की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

1. **उपस्थिति** - संलग्न।

2. वर्ष 2014-15 में कृषि रोड मैप के परफॉरमेंस इंडिकेटर के प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण की गई। विभागवार प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है,

3. **कृषि विभाग** -

वित्तीय वर्ष 2014-15 में धान का बीज विस्थापन दर में 44 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 38.75 प्रतिशत, गेहूँ की बीज विस्थापन दर में 36 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 35.58 प्रतिशत, दलहन के बीज विस्थापन दर में 25 प्रतिशत के विरूद्ध 14 प्रतिशत, तेलहन के बीज विस्थापन दर में 50 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 49 प्रतिशत की उपलब्धि हुई है। सघन रोपन विधि से बाग की स्थापना में 7040 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 5555 एकड की उपलब्धि हुई। जैविक सब्जी का क्षेत्र के अंतर्गत 20232.5 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 12542 एकड़ की उपलब्धि हुई, किसान समूह/फेडरेशन का गठन के अंतर्गत 5340 लक्ष्य के विरूद्ध 4420 की उपलब्धि हुई, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई 204974 के विरूद्ध 149669 की उपलब्धि हुई, जैव उर्वरक में 10.4 लाख एकड लक्ष्य के विरूद्ध 7.79 लाख एकड की उपलब्धि हुई, गोबर/बायो गैस मे 5000 लक्ष्य के विरूद्ध 4953 की उपलब्धि हुई, पावर टिलर के अंतर्गत 7500 लक्ष्य के विरूद्ध 2043 की उपलब्धि हुई, जीरो टिलेज के अंतर्गत् 6000 लक्ष्य के विरूद्ध 1348 की उपलब्धि हुई, कम्बाईन हार्वेस्टर के अंतर्गत् 350 लक्ष्य के विरूद्ध 164 की उपलब्धि हुई, धान की श्री विधि का प्रत्यक्षण के अंतर्गत 500000 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 478816 की उपलब्धि हुई, धान की श्री विधि का गैर प्रत्यक्ष्ण के अंतर्गत 2000000 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 921694 एकड की उपलब्धि हुई, धान की श्री विधि का कुल आच्छादन 2500000 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 1400510 एकड की उपलब्धि हुई। जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण के अन्तर्गत 292719 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 260158 एकड की उपलब्धि हुई तथा गेहूँ की श्री विधि से प्रत्यक्षण के अन्तर्गत 78648.5 एकड लक्ष्य के विरूद्ध 71325 एकड़ की उपलब्धि हुई। जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत दक्षिण बिहार में मक्का की खेती के अन्तर्गत 150000 एकड़ के विरूद्ध 130329 एकड़ की उपलब्धि हुई है। मेड़ पर अरहर की खेती में 15625 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 15089 एकड़ की उपलब्धि हुई है। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि कृषि यंत्रों, गोबर गैस की कम

उपलब्धि की समीक्षा विभाग द्वारा किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष के लिए योजना की स्वीकृति तत्काल की जाय। गत वर्षो से अवशेष लक्ष्य को इस वर्ष पूरा किया जाय।

4. **सहकारिता विभाग** -

इस विभाग के कुल तीन कार्यमद परफॉरमेंस इंडिकेटर में सम्मिलित है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि (पैक्स एवं व्यापार मंडल) में 2014-15 में 3.261 लाख मैट्रिक टन के विरूद्ध 0.621 लाख मैट्रिक टन, भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि (बिहार राज्य भंडारण निगम) में 4.70 लाख मैट्रिक टन के विरूद्ध 0.45 तथा परिसंस्करण इकाई की स्थापना (चावल मिल सह गैसीफायर) में 70 के विरूद्ध 27 की उपलब्धि हुई है। निदेश दिया गया कि राज्य भंडार निगम द्वारा गोदाम निर्माण की समीक्षा सहकारिता विभाग द्वारा की जाय तथा गोदाम निर्माण में तेजी लाई जाय।

5. **ऊर्जा विभाग** -

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की औसतन उपलब्धता अन्तर्गत 1300 मेगावाट लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 1200 मेगावाट, नये 33/11 के0भी0 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण के लक्ष्य 75 के विरूद्ध 29, 11 के0भी0 नये लाइन के निर्माण के लक्ष्य 12000 कि0मी0 के विरूद्ध 7089.04 कि0मी0, विधुत वितरण में ट्रासफर्मर की क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य 750 एम0भी0ए0 के विरूद्ध 839.07 एम0भी0ए0 तथा ग्रामीण क्षेत्र के पावर ट्रासफर्मर की क्षमता में वृद्धि 1241 एम0भी0ए0 लक्ष्य के विरूद्ध 1182.40 एम0भी0ए0 तथा सौर उर्जान्वित निजी नलकूपों में 600 लक्ष्य के विरूद्ध 600 की उपलब्धि हुई है। निदेश दिया गया कि सौर्य उर्जान्वित नलकूप की सूची उर्जा विभाग द्वारा कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6. **पर्यावरण एवं वन विभाग** -

सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की संख्या में 553.93 लाख लक्ष्य के विरूद्ध 363.14 लाख, वन क्षेत्रों में जलछाजन का विकास 57654 हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 42349.36 हे0, नदी तटबंध एवं नहर किनारे वृक्षारोपण में 3055 कि0मी0 लक्ष्य के विरूद्ध 365.30 कि0मी0, कृषि वानिकी में 59.29 लाख पौधों के विरूद्ध 185.19 लाख तथा वृक्ष संरक्षण योजना में 68196 लक्ष्य के विरूद्ध शून्य की उपलब्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त योजना उद्व्यय की मांग की गई। इस क्रम में सर्वप्रथम उपलब्ध राशि के व्यय करने का निदेश दिया गया।

7. <u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u> -

वर्ष 2014-15 में 10.305 लाख मेट्रिक टन खाध् भंडारण के गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 5.65 लाख मेट्रिक टन है। विभाग द्वारा अतिरिक्त उद्व्यय की आवश्यकता बताई गई। चालू परियोजनाओं को पूरा करने का निदेश दिया गया।

8. <u>उद्योग विभाग</u> -

शीत भंडारण क्षमता में 1000000 मेट्रिक टन के विरूद्ध 243002 मेट्रिक टन, राइस मिलिंग क्षमता में 22.13 लाख मेट्रिक टन/ वर्ष लक्ष्य के विरूद्ध 14.628 लाख मेट्रिक टन/वर्ष तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाई (राइस मिल को छोड़कर) में 28 लक्ष्य के विरूद्ध 35 की उपलब्धि हुई। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना में संतोषजनक उपलब्धि है, परन्तु कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में काफी कम है। राईस मिल के सत्यापन को तेजी से पूरा करने का निदेश दिया गया।

9. <u>लधु जल संसाधन विभाग</u> -

सिंचाई क्षमता के नये सृजन में 5.56 लाख हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 0.31454 लाख हे0, सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन में 1.1935 लाख हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 0.0696 लाख हे0, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत 105030 लक्ष्य के विरूद्ध शून्य, नया सामुदायिक निजी नलकूप के अन्तर्गत 1.2472 लाख हे0 के विरूद्ध 0.1121 लाख हे0 तथा अहर-पईन उद्ववह, ए0आई0बी0पी0, मध्यम सिंचाई योजना में 1.040 लाख हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 0.20244 लाख हे0 की उपलब्धि हुई। शताब्दी नीजी नलकूप योजना में तेजी लाई जाय। सौर्य उर्जान्वित नलकूप में बाह्य एजेंसी द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी प्राप्त की जाय तथा अच्छे अनुभवों को राज्य में लागू किया जाय। योजनाओं को तुरंत स्वीकृत किया जाय।

10. <u>जल संसाधन विभाग</u> -

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन में 135754 हे0 लक्ष्य के विरूद्ध 4040 हे0, ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन में 214782 हे0 के विरूद्ध 129864 हे0 तथा जल निस्सरण योजनाओं द्वारा जल जमाव से मुक्ति में 9104.5 हे0 के विरूद्ध 1077 हे0 की उपलब्धि हुई। भौतिक उपलब्धि संतोषप्रद नहीं है। लम्बित

योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता पर पूरा किया जाय। भूमि अधिग्रहण के मामलें का त्वरित समाधान किया जाय।

**11. <u>राजस्व विभाग</u> -**

हवाई फोटो ग्राफी कार्य समाप्त किये गये जिलों की संख्या 10 जिला यथा बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णियां, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल- 7918 राजस्व ग्राम। 2 जिला यथा नालंदा, शेखपुरा (आंशिक रूप से) - 57 राजस्व ग्राम। भारत सरकार से सुरक्षा जांच हेतु पी0 प्रोसेसिंग के लिए मानचित्र के अन्तर्गत बेगूसराय, लखीसराय एवं खगड़िया जिला के 1577 राजस्व ग्राम तथा सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा के राजस्व ग्रामों के डाटा के Security Vetting का कार्य सम्पन्न। नक्शा निर्मित करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। 04 जिलों यथा अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं सहरसा के हवाई फोटो ग्राफी को चेक लिस्ट के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित कर दिया गया है तथा Security Vetting के लिए तारिख देने का अनुरोध किया गया है। जमीनी सत्यापन हेतु प्राप्त कुल मानचित्रों की संख्या 689 राजस्व ग्राम का री-सर्वे मानचित्र प्राप्त। खानापुरी के अन्तर्गत 234 राजस्व ग्राम तथा प्रारूप प्रकाशन के अन्तर्गत 77 राजस्व ग्राम की उपलब्धि हुई है। अन्तिम प्रकाशन के अन्तर्गत प्रकाशित अभिलेख में 2 ग्राम तथा प्रकाशन हेतु तैयार अभिलेख में 8 ग्राम की उपलब्धि हुई है।

**12. <u>ग्रामीण कार्य विभाग</u> -**

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अन्य राज्य योजना सहित) में 2300 कि0मी0 पथ के लक्ष्य के विरूद्ध 1891.17 कि0मी0, 2400 मी0 पुल के लक्ष्य के विरूद्ध 1976.60 मी0 की उपलब्धि हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 10200 कि0मी0 पथ के लक्ष्य के विरूद्ध 3363.05 कि0मी0, 600 मी0 पुल के लक्ष्य के विरूद्ध 367.89 मी0 की उपलब्धि हुई। भारत सरकार से इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के लिए प्राप्त प्रथम किस्त की राशि का सामंजन राज्यांश के रूप में किया गया है क्योंकि गतवर्ष भारत सरकार से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक राशि का व्यय किया गया था। निदेश दिया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग से समन्वय कर अतिरिक्त उद्व्यय/बजट उपबंध प्राप्त किया जाय।